(c) what will be its impact on the private export and other trade activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) and (b). The Government is considering a suggestion that the State Trading Organisations should undertake a substantial amount of actual trading on their own account including buying, selling, stocking, etc., *vis-a-vis* the conventional back-to-back contracts entered into by State Trading Organisations at present.

(c) The Corporation's proposed activity will be supplementing the efforts of the private export trade. It will assist particularly the small scale stocking, etc., *vis-a-vis* the convenbase and upgrading the quality and the packaging in order to meet the international standards

राजस्थान में चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें

6020. श्री चतुर्भुज : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में चल रही उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित की गई है और उनमें से प्रत्येक योजना के लिये राजस्थान सरकार को कितना सहायता अनुदान दिया जा रहा है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : यह मंत्रालय राजस्थान सरकार को दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् (1) उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की योजना और (2) राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में उपान्त धन (मार्जिन मनी) सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत सहायता दे रहा है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1977–78 के दौरान राजस्थान सरकार को लगभग 12.87 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी गई है। यह वित्तीय सहायता 2 बहु-विभागी भंडार एक भरतपुर में और एक अलवर में, दो छोटे (मीनी) बहु-विभागी भंडार जयपुर में और 50 छोटी छोटी शाखायें उन स्थानों में जहां अधिकतर कमजोर/असंगठित क्षेत्रों के लोग रहते हैं, खोलने के लिए दी गई है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	लाख रु०
(i) अंशपूंजी अंशदान	9.20
(ii) फर्नीचर तथा फिक्सचर्स के लिए ऋण	1.58
(iii) आर्थिक सहायता जिसमे प्रबंधकीय आर्थिक सहायता भी शामिल है	2.09
योग	12.87

2. अब तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रहा था, जिसके अंतर्गत वह राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में उपान्त धन (मार्जिन मनी) सहायता दे रहा था। राज्य सरकारों द्वारा यह सहायता आगे थोक विक्रेता के रूप में कार्य कर रही सहकारी विपणन समितियो को केवल इस रूप में दी जा रही थी—(क) निर्बन्ध (क्लीन) अंशपूंजी अथवा (ख) न्यूनतम ब्याज अथवा लाभ संबंधी किसी शर्त रहित प्रतिदाय

अंशपूंजी अथवा (ग) ब्याज की उस रियायती दर पर अर्द्ध-इक्विटी जो संघ द्वारा अंशपूंजी पर आम तौर पर दिये जाने वाले लाभांश से अधिक नहीं होगी, ताकि वे उर्वरकों और अन्य कृषि निवेशों की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए बैंक वित्त ले सकें। यह स्कीम चौथी योजना में शुरू की गई थी और 31 अगस्त, 1977 तक चालू रही। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राजस्थान सरकार को कुल 78.775 लाख रुपये की सहायता दी है, जिसका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	लाख रुपये में
1973–74 . .	3.00
1974–75 . .	32.50
1975–76 . .	23.275
1976–77 . .	शून्य
1977–78 तक .	20.00
	78.775

इस सहायता के फलस्वरूप, राजस्थान में सहकारी समितियों, उर्वरकों और अन्य कृषि निवेशों का वितरण कार्य 1973–74 के 1230 लाख रुपये से बढ़ाकर 1975–76 में 2904 लाख रुपये कर सकीं।

अब यह योजना समाप्त कर दी गई है। इसे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर उपान्त धन के लिए आग्रह किये बिना बैंकों द्वारा उर्वरकों के लिए धन दिया जा रहा है।

पर्यटन केन्द्रों के लिए जनता होटल

6021. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे पर्यटक केन्द्रों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में जनता होटल स्थापित करने का है तथा इसके लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में जनता होटल स्थापित करने का निर्णय किया है और क्या सरकार ने खजुराहो और ओरछा पर्यटक केन्द्रों में भी जनता होटल स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या पर्यटक केन्द्रों में जनता होटलों के अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी उपलब्ध कराई जायेंगी जैसा कि स्विमिंग पूल और हैली काप्टर सेवा; और

(घ) क्या खजुराहो में स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य इस बीच आरम्भ हो गया है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). 1978–83 की अवधि वाली पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के चार महा नगरों में जनता होटलों का निर्माण करने पर बल दिया गया है। 1978–79 के दौरान नई दिल्ली में जनता होटल परियोजना के लिए 50 लाख रुपए के व्यय का अनुमोदन किया गया है। मध्य प्रदेश के केन्द्रों तथा अन्य उन केन्द्रों का निर्धारण, जहां केन्द्रीय क्षेत्र में जनता होटल स्थापित किए जाएंगे, एक सर्वेक्षण करने के बाद किया जाएगा, जो इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर निर्भर करेगा।